

संपादकीय

ईडी को फटकार

तमिलनाडु की खुदरा शराब कंपनी टीएसएमएसी के खिलाफ धनशोधन की जांच की ईडी की स्वतः स्फूर्त कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की और यहाँ तक कह डाला कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सारी सीमाएं पार कर रहा है और शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। राज्य सरकार और टीएसएमएसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति अॅग्स्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से दो टूक कहा, प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं पार कर रहा है। धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की सख्त धाराओं के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कई पीठ पहले भी ईडी को जमकर फटकार लगा चुकी हैं। विपक्षी दल तो ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ अक्सर विरोध जताते ही रहते हैं। पीठ ने राज्य सरकार और टीएसएमएसी की दलीलों पर गौर करते हुए टीएसएमएसी के खिलाफ जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार और टीएसएमएसी का तर्क है कि शराब दुकानों के लाइसेंस देने में कथित अनियमिताओं को लेकर हम पहले ही आपराधिक कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। 2014 से अब तक इस मामले में 41 प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं और अब ईडी बीच में कूदकर टीएसएमएसी पर ही छापेमारी कर रही है। इस पर पीठ ने फटकार लगाते हुए ईडी से तीखा सवाल किया कि आप राज्य द्वारा संचालित टीएसएमएसी पर कैसे छापा मार सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने संवैधानिक अधिकारों और संघीय ढांचे के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपनी याचिका में कानून के व्यापक प्रश्न उठाए हैं, जिनमें संघवाद का मुद्दा भी शामिल है। जिसमें ईडी अपने दायरे से बाहर जाकर और राज्य के अपराध की जांच करने के अधिकार को हड्डपने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार की दलील है कि टीएसएमएसी को इन प्राथमिकी में से किसी में भी आरोपी नहीं बनाया गया है और कई मामलों में वह शिकायतकर्ता है। दरअसल, यह मामला राज्य और केंद्र सरकार के बीच काफी समय से चल रही चांदमारी का ही एक और नमूना है जिसमें ईडी तो कभी सीबीआई निशाने पर आते रहते हैं। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए ईडी अपनी कार्यपाली में बदलाव लाएगी।

आलेख

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा मध्यप्रदेश

के.के.जोशी

मध्यप्रदेश देश के हृदय स्थल में बसा एक ऐसा राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज पूरे देश में नई मिसाल कायम कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार स्व-सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनाया है। स्व-सहायता समूह न केवल ग्रामीण और शहरी महिलाओं को अर्थात् रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी योजनाकी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश ने कई अपलब्धियों को हासिल किया है। सरकार की अनेक नीतियां और योजनाएं महिलाओं के उद्धार में सहायक सिद्ध हो रही हैं। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है। अत्यंत मान में, राज्य में 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 62 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। ये समूह महिलाओं को अर्थात् स्वतंत्रता, कौशल विकास, और सामुदायिक नेतृत्व के अवसर प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मानना है कि स्व-सहायता समूह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का साधन हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी एक जन-आंदोलन है। मध्यप्रदेश सरकार ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं जिनका प्रभाव राज्य के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना ने हजारों महिला समूहों को कम ब्याज पर अपूर्ण दिलाकर उनके छोटे-छोटे व्यवसायों को सहारा दिया है। अब महिलाएं न सिर्फ घर चला रही हैं, बल्कि दसरों को भी रोजगार दे रही हैं।

। अब तक 30 हजार 264 महिला समूहों और 12 हजार 685 महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में 648.67 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 1551.86 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उनके खातों में पहुंच रही है। इससे न केवल आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही है बल्कि महिलाएं डिजिटल युग की सहभागी भी बन रही हैं। इस योजना में 1.27 करोड़ महिलाओं को अब तक 5,329 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। इसके प्रतिरिक्ष, 25 लाख महिलाओं को 450 रुपये में गैंग सिलेंडर रीफिलिंग लिए 882 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके परिवारों व बचत को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2024-25 में 2 लाख 73 हजार 605 बालिकाओं का पंजीकरण हुआ है और लगभग 223 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति यूनि-पे के जरिए वितरित की गई। अब तक कुल 50 लाख 41 हजार 810 बेटियां इस योजना का हिस्सा हैं। राज्य सरकार द्वारा नारी शक्ति मिशन के तहत जिला, जिले विभिन्न योजना और ग्राम स्तर पर 100 दिवसीय जागरूकता हम होंगे कामयाब निर्धारण चलाया गया। इसमें प्रदेश में जेंडर संवादों, घेरू हिंसा, बाल विवाह, सायबर सुरक्षा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की महिलाओं को न केवल जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें अपने प्रतिक्रियाओं के लिए खड़ा होना भी सिखाया गया। मध्यप्रदेश सरकार ने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 1 लाख से अधिक महिलाओं को सिखाया दी दी बनाया है। सरकार का लक्ष्य 5 लाख स्व-सहायता समूहों का माध्यम से 62 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। यह पहल नारीण महिलाओं को उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में वितरित कर रही है। मध्यप्रदेश में 850 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 75 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग में कार्यरत महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे उनकी मासिक आय में बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य सरकार ने नारी सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता में रखा है। पुलिस बल में महिलाओं की विवरण बढ़ाई गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में विवर सजा का प्रावधान किया गया है। महिला हेल्पलाइन और महिला लिस्ट स्टेशन जैसी सेवाओं को भी मजबूत किया गया है।

डा. अश्विनी महाजन

अमरीकी राष्ट्रपति टैरिफ़ - एक अवसर

लगाया गया। इसके अलावा, अमरीकी प्रशासन ने धमकी दी कि अगर कोई देश भी अमरीका से आयात पर जवाबी कार्रवाई कर टैरिफ बढ़ाता है तो वे भी टैरिफ और बढ़ा देंगे। इस सदर्थ में, चीन की जवाबी कार्रवाई और अमरीका से आयात पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बाद, ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयात पर उसके बाद 104 प्रतिशत टैरिफलगाने का फैसला किया। हालांकि, एक हफ्ते से भी कम समय में, 8 नवबरी को ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कदम वापस ले लिए और पारस्परिक टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया, और कहा कि अब 75 देशों पर मात्र 10 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क ही लगेगा, लेकिन चूंकि चीन ने जवाबी कार्रवाई की है, ट्रंप ने उस पर पहले 104 प्रतिशत और फिर 145 प्रतिशत और उसके बाद तो 245 प्रतिशत का पारस्परिक टैरिफलगा दिया है। हाल ही में चीन और अमरीका में कुछ सहमति बनने के बाद अमरीका ने चीन पर टैरिफ घटाकर 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है गलत : हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह तर्क देते हैं कि दूसरे देश अमरीकी सामानों पर ज्यादा टैरिफलगाते हैं, जबकि अमरीका विदेशों से आने वाले सामान पर कम टैरिफलगाता है। इससे अमरीका को नुकसान होता है, क्योंकि अमरीकी सामान दूसरे देशों में जाकर महंगा हो जाता है, जिससे अमरीकी सामान कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाता है। उनका कहना है कि उन्हें अमरीका में उद्योगों को पुनः स्थापित कर अमरीका को पुनः महान बनाना है। लेकिन उनका यह तर्क

इसलिए गलत है क्योंकि भारत समेत दूसरे देश अमरीकी सामान पर अधिक टैरिफ डब्ल्यूटीओ में हुए समझौतों के अनुरूप लगाते हैं। उदाहरण के लिए भारत अपने देश में आने वाले सामानों पर 50.8 प्रतिशत भारित टैरिफ लगाने का अधिकारी है। हालांकि भारत वास्तव में मात्र 6 प्रतिशत भारित टैरिफ ही लगाता है। भारत समेत अन्य विकासशील देशों के ज्यादा टैरिफ लगाने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि डब्ल्यूटीओ में हुए समझौतों में भारत समेत अन्य विकासशील देशों को मात्रात्मक नियंत्रण लगाने अपने लघु उद्योगों के संरक्षण करने, कृषि के अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों से अलग रखने, अपना बौद्धिक संपदा एवं विदेशी निवेश को नियमित करने हेतु कानून बनाने की स्वतंत्रता समेत कई अधिकारों से विचित होना पड़ा था। इसके बदले में उन्हें अमेरीका और अन्य विकसित देशों की तुलना में ज्यादा टैरिफ लगाने का अधिकार मिला था। ट्रॉप द्वारा टैरिफ युद्ध के बाद वह अधिकार भी छिन रहा है। डब्ल्यूटीओ से हुआ नुकसान : यह साबित हो चुका है कि बहुपक्षीय समझौते भारत जैसे विकासशील देशों के लिए शुभ नहीं हैं। अब समय आ गया है कि जब अमरीका जैसे विकसित देश डब्ल्यूटीओ की अवहेलना कर रहे हैं, तो हमें भी डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स समेत अन्य शोषणकारी समझौतों से बाहर आने की रणनीति बाबरे में सोचना चाहिए। ध्यातव्य है कि डब्ल्यूटीओ से पहले, भारत लगभग 10000 वस्तुओं के आयातों पर मात्रात्मक नियंत्रण (क्यूआर) लगाता था, लेकिन

डब्ल्यूटीओ समझौतों के कारण वह संभव नहीं रहा। डब्ल्यूटीओ के विघ्टन के बाद अब मात्रात्मक नियंत्रण लगाना संभव हो सकेगा, जिससे हमें अपने उद्योगों को संरक्षित एवं संवर्धित करना संभव हो सकेगा। द्विपक्षीय समझौतों की जरूरत : नए परिदृश्य में, भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के बजाय द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के साथ अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाना चाहिए। हालांकि अमरीका और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते समय, राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर हमारे किसानों और छोटे उद्यमियों की। हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में, सरकार व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय किसानों के हितों और उनकी आजीविका की रक्षा कर रही है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से कृषि को बाहर करना हो, या डेयरी और कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की चिंताओं के कारण क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आसीईपी) से बाहर आना हो। जहां तक कृषि और लघु उद्योग का सवाल है, इस नीति को जारी रखने की जरूरत है, खासकर जहां किसानों और उद्यमियों की आजीविका प्रभावित हो रही हो। इसके अलावा, भारतीय रूपए में विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय है। हालांकि, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रणाली को हमारे देश पर दबाव बनाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल न करने दिया जाए। पूरी दुनिया भू-आर्थिक विखंडन के दौर से गुजर रही है और इस परिदृश्य में सफलता की कुंजी 'राष्ट्र प्रथम' की नीति है। नई संभावनाएं : एक तरफ जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और दूसरे देशों पर शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं और डब्ल्यूटीओ नियमों को दरकिनार किया जा रहा है, नए परिप्रेक्ष्य में नई संभावनाएं भी जन्म ले रही हैं। चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने विभिन्न देशों पर अलग-अलग शुल्क लगाने का निर्णय किया है। चीन पर अधिक शुल्क लगाने और चीनी सामान अमरीका और यहां तक कि यूरोपीय देशों द्वारा भी विभिन्न प्रकार की रुकावटें लगाने से भारत के लिए इन देशों में संभावनाएं बेहतर हुई हैं। यूरोपीय देश जो भारत से सामान्यतः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य प्रकार के सहयोग से बचते थे।

तं वाक्

डॉ. कशेव पाण्डे

हर साल 31 मई का विश्व तबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक प्रयास है जो हमें चेताता है, जिसके द्वारा तबाकू का उपभोग रोका जाए। यह अवसर हमें आत्मचिंतन करने के साथ-साथ जनजागरूकता फैलाने का भी मौका देता है कि कैसे एक छोटी-सी आदत पूरे जीवन को निगल सकती है। आइये, जानते हैं, इस दिवस का महत्व, इसके पाँचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तबाकू के दुष्परिणाम और इस वर्ष की खास थीम। तबाकू का सेवन चाहे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या किसी अन्य रूप में किया जाए, यह शरीर के लिए धीमा जहर है। इसके सेवन से सबसे अधिक प्रभावित होता है हमारा श्वसन तंत्र और हृदय विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल दुनियाभर में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तबाकू जनित बीमारियों के कारण होती है। इन मौतों में से लगभग 12 लाख लोग वे होते हैं जो स्वयं तबाकू का सेवन नहीं करते, बल्कि परोक्ष रूप से यानी पैसिव स्पोकिंग से प्रभावित होते हैं। तबाकू के सेवन से लाखों लोग अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इनमें फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक, दमा, ब्रॉकाइटिस, उच्च रक्तचाप हार्ट फेल्ड्योर, क्रॉनिक ब्रॉकाइटिस, क्रॉनिक ऑस्ट्रटिक्टिव पल्मोनरी डिजीज.

अस्थमा, दात परगना, मसूड़ा म सक्रमण, सकद धब्ब जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। इनके अलावा गर्भवती महिलाओं में झूण की वृद्धि में बाधा, समय से पहले प्रसव, नवजात की मृत्यु जैसी जानलेवा बीमारियां शामिल हैं। भारत में भी तंबाकू एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। देश में हर साल लगभग 13 लाख लोग तंबाकू के कारण असमय काल के गाल में समा जाते हैं। यह कुल मृत्यु दर का लगभग 9.5 प्रतिशत है। इनमें से लगभग 10-12 लाख मौतें धूप्रापण से होती हैं, और रेष गुटखा, पान मसाला, हुक्का जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों से। जबकि मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 90 हजार से एक 1 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन के कारण होती है। राज्य में पुरुषों के बीच तंबाकू सेवन की दर 40 प्रतिशत से अधिक है, जबकि महिलाएं की लगभग 10 से 12 प्रतिशत। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, अगर तंबाकू पर सख्ती से नियंत्रण न लगाया गया, तो आने वाले दशकों में तंबाकू से हर साल 1 करोड़ मौतें हो सकती हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत विकासशील देशों में होंगी, उनमें भारत सबसे प्रमुख है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत 1987 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पहली बार 7 अप्रैल 1988 को मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 31 मई कर दी गई। इसका उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के

मीठा ज़हर और धीमी मौत

भाषा में शालीनता क्यों गायब हो गई?

कविता सिसोदिया

आज के युग में पढ़े-लिखे उच्च पद पर आसीन महानुभाव भी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और जो मुंह में आ रहा है, बोल रहे हैं। एक मंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिस्ट्रिक्शन को लेकर विवादित बयान दिया गया। उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा गया। राजनीति-सोशल मीडिया का सच है एक छोटी सी पुरानी कहानी है कि एक बार एक सैनिक जंगल में भटक गया। वह अपने राजा और मंत्री को ढूँढ़ता-ढूँढ़ता जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंचा, जहां एक अंधा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस सैनिक ने उसे देखकर कहा कि मैं भटक गया हूँ, क्या आपने राजा या मंत्री को इस जंगल से जाते हुए देखा है। तो अंधे ने कहा कि वैसे तो मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, पर बता सकता हूँ कि पहले यहां से राजा, पिर मंत्री और पिर उसके बाद नौकर एक-दूसरे को ढूँढ़ते हुए निकले हैं। सैनिक ने कहा कि आप तो देख नहीं सकते पिर कैसे पता चला कि वे राजा, मंत्री और नौकर थे। तो अंधे व्यक्ति ने कहा पहले यहां से राजा जी गुजरे, उन्होंने मुझे पूछा सूरदास जी क्या आपने यहां से किसी बोड़े की टाप सुनी है। पिर मंत्री आया। उसने कहा जरा सुनिए अंधे क्या तुमने यहां से हमारे राजा या मंत्री को जाते देखा है। भाषा की शालीनता से मैं बिना आंखों से भी पहचान गया। सूरदास जी कहने वाला राजा था। उसने सुनिए महोदय कहने वाला मंत्री था अब आओ! अंधे, कहने वाला नौकर था। उसका प्रकार जो संस्कारित धराने से होगा, उसका उतना ही सभ्य, शालीन और उदार होता रहा। शिक्षित, संस्कारित विद्वान् तीसरे स्तर पर रहा। भाषा कभी नहीं बोल पाता। अपमानजनक भाषा बोलने वाले को प्रत्युत्तर देने के लिए उसे भी उसी स्तर तक नीचे गिरना पड़े। वैसा वह कर नहीं पाता और गहरी पीढ़ी झेलता है। शब्द ब्रह्म स्वरूप होते हैं। एक बार प्रस्फुटि होने के बाद उनकी बाप ठीक वैसे ही नहीं होती जैसे तरकश निकले तीर की। प्राचीन युग से ही पुराणों की लड़ाई में नारी का अपमान और शोषण किया जाता रहा है। उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं और वह बेचारी बिना कसूर के पिस्तॄ है। मूर्ख और असभ्य लोग ही मां-बहनों की पीछे पड़ जाते हैं। साधारण नारी या लड़की का राह में अकेले चलना तो मुश्किल ही नहीं है। शब्दों का प्रयोग करते हैं। परंतु आज यह में पढ़े-लिखे उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं।

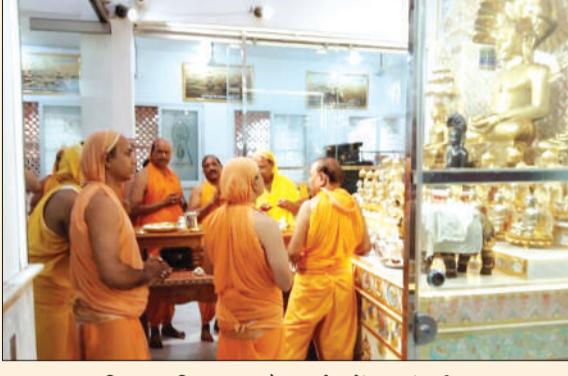


महानुभाव भी भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और जो मुँह में आ रहा है, बोल रहे हैं। एक मंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया गया। उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा गया। आज की राजनीति और सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोगों का वर्ग बढ़ता जा रहा है जो बिना सोचे-समझे जो जुबान में आ रहा है, उसे बोल रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उन्हें इन अपशब्दों पर कोई पश्चाताप नहीं है। एक ऐसा वर्ग जो सभ्यता के नाम पर कलंक है। एक शिक्षित की भाषा मर्यादित होती है। मानव ने पृथ्वी लोक पर इतना विकास कर लिया, पिर भी वह सभ्य और सुसंस्कृत नहीं बन सका तो बहुत ही दख की बात है। इन लोगों को भगवान का भी डर नहीं है। जब इनका विपुरुष को गाली देकर नहीं भरता, तो नीचता की सारी हंदें पार करके उनकी मबहन या बेटी पर इतने घटिया चरित्रहार और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि बड़े से बड़ा गुंडा भी हैरान रह जाए। स्वर की देवी सरस्वती है तो क्या उसे सरस्वती मां का अपमान नहीं है जिनसे स्वर और विद्या का वरदान मिला। इस भारत कोविड-19 महामारी की विनाशक दूसरी लहर से गुजर रहा था, गंगा में सैकड़े लाशें तैरती देखी गई। बहुत ही भयंकर रुक्मिणी की गंगा की दूसरी लहर से देश गुजर रहा था। तब गुजरात की प्रधानमंत्री संवेदनशाल कवियत्री पासल खक्कर द्वारा गुजराती में लिखी गई कविता : ‘एक सब मर्दें बोले सब कछु चंगा-चंगा/राजा-

तुम्हरे रामराज में शब वाहिनी गंगा।' इस मूल गुजराती कविता का हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, अंग्रेजी, यहां तक कि जर्मनी में भी अनुवाद किया गया तो अश्लीलता में माहिर इस वर्ग ने सोशल मीडिया पर अश्लील व्यक्तिगत टिप्पणियां पोस्ट करके उन्हें इतना परेशान किया कि उन्हें अपना फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक करना पड़ा। विदेश सचिव विक्रम मिस्ट्री भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफ्यर का ऐलान करने के बाद उनको ट्रोलर ने सोशल मीडिया में इतनी गालियां दी और उनके परिवार और यहां तक कि उनकी बेटी पर भी अश्लील संदेशों की बौछार लगा दी। इस सबसे परेशान होकर उन्होंने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर दिया। हिमांशी नरवल शादी के केवल 6 दिन बाद ही पहलगाम नरसंहार में विधवा हो गई थी, उसका दोष यही था कि जब कश्मीर में आतंकवादियों के घरों पर बुलडोजर चलने का समाचार सुना तो उसने शार्ति की अपील करते हुए कहा कि हमें न्याय चाहिए, पर किसी बेकसूर मुसलमान और कश्मीरी को टारगेट न किया जाए। बस फिर क्या था, गंदगी उगलने वाले गिर्द की तरह टूट पड़े और उन्हें सोशल मीडिया में जमकर गालियां दी गईं। चरित्र पर बहुत ही बेहदा लांच्छन लगाए गए।

संक्षिप्त समाचार

श्रुत स्कंध महामंडल विधान



जबलपुर (विश्व परिवार)। जैन दर्शन में श्रुतपंचमी का बहुमहत्व है, प्रभु द्वारा प्रतिपादित आगमश्रुत को जिनवाणी के रूप में मुनिराजों द्वारा संकलन कर जैनमानस के लिए प्रस्तुक किया, जो आज जैन दर्शन का प्रमुख है। यह पर्व जैन धर्म का एक वर्षावास और ऐतिहासिक पर्व है, जिसे 'ज्ञान पंचमी' और 'प्राकृत भाषा दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है और यह आगमों और शास्त्रों की बंदा, उनकी शुद्धता और संरक्षण की भावना से जुड़ी है। ग्रंथों में वर्णित हैं कि इस दिन आचार्य धर्मसेन के निर्देशन में आचार्य पुष्पदत्त और भूतविल ने पहली बार जैन धर्म के मौखिक ज्ञान को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ को 'षट्खंडितम्' कहा जाता है, जो जैन धर्म का मूल स्तंभ है। इससे पहले भगवान महावीर की वाणी केवल मौखिक रूप से लिखी थी और संरक्षण की भावना से जुड़ी है। ग्रंथों में वर्णित हैं कि इस दिन आचार्य धर्मसेन के निर्देशन में आचार्य पुष्पदत्त और भूतविल ने पहली बार जैन धर्म के मौखिक ज्ञान का संरेख दिया जीव सिद्धांत और कम सिद्धांत की बात जैन सिद्धांत में आई है। श्रुत पंचमी की वर्षा परस्परा प्रभु और गुरु के बीच से होकर के हम अंधकार से जुड़ी है। यह पर्व जैन धर्म और भूतविल ने पहली बार जैन धर्म के मौखिक ज्ञान को ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। इसके स्मृति में श्रुतपंचमी मनाई जाती है।

हनुमानताल मार्ग में मंगली बज्रिया स्थित वर्तमान नव स्वरूप में लाल मंदिर जी के रूप में प्रतिष्ठित श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन बरियाला मंदिर जी में आज प्रातः संगीतमय मां जिनवाणी की आराधना बड़े भक्तिभाव से तहत हुई। श्रुत स्कंध महामंडल विधान का आयोजन किया गया, अध्यक्ष सुनील सिंहदे ने बतलाया कि आज सुबह से धार्मिक पूजन एवं श्रुत स्कंध वंत्र जी का अभिषेक विधानाचार्य शंशाक धैया, दयनगर के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। संपूर्ण बरियाला ट्रैट कमेटी द्वारा विधान में सम्प्रसिद्ध समस्त त्रिविलालों का आधार प्रकट किया गया।

शोक सभा में युग पुरुष सुरेंद्र पवैया को दी श्रद्धांजलि

ललितपुर (विश्व परिवार)। सकल दिगम्बर जैन समाज तालेबहूट की एक शोक सभा में रामलीला मैदान विनासी जयकमार जी पवैया

के बड़े भाई एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी व समाजसेवी सीरेभ पवैया के पूर्ववाची पिता जी व दानवीर हिंदूद कुमार जिनेंद्र पवैया के चाचाजी धर्मप्रेषी युग पुरुष सुरेंद्र कुमार पवैया का कड़ेसरा बालों के आकर्षिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। श्रद्धांजलि देने वालों में चौधरी तुमराम, डॉ. मंदेंद्र जैन, अनित चौधरी, राकेश मोदी, देवेंद्र बसार, प्रवीन कुमार, अरविन्द भंडारी, कमलेश सिसी, अल्पा कुमार, सजल मोदी, यशपाल जैन, अजय जैन, सुधीर कुमार, रीतेश चौधरी, कपिल मोदी, विकास पवा, रोहित जैन, जिनेंद्र कुमार, धरेंद्र जैन, शैलेश कुमार, आदेश मोदी, अधिषेक मिठाया, प्रिंस जैन, रामध विराज, अधिषेक जैन आप्रसुत रहे। वहाँ पांचालिंगि क्षेत्र प्रब्रह्म समिति की शोक सभा में कार्यक्रमों सदस्य परम संस्करण प्रतीक्षा पवैया के पूर्ववाची सुरेंद्र कुमार पवैया के निधन पर जानन्द जैन, उत्तमचंद्र तुमराम, आनंद जैन, यजुकल जैन, जनवान पवा, विकास भंडारी, आकाश चौधरी, पंकज भंडारी, सीरेभ जैन, संदीप, अजय, अमन, अमित जैन आदि ने श्रद्धांजलि समर्पित की।

प्रदेश में दो करोड़ 75 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा

रायपुर (आएनएस)। 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अधियान के तहत प्रदेश में करोड़ 2.0 करोड़ 75 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधों की उपलब्धा विभाग के नर्सरीयों और विभागीय जैतों से सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अवसर पर जानवायु परिवर्तन मंत्री केंद्र कर कर्पुर में 'एक पेड़ मां के नाम' अधियान की समीक्षा की। बैठक में अधियान के तहत शासकीय विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वक्षप्रोपण के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों से 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अधियान के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भारतीय छात्र अब मेडिकल शिक्षा के लिए किर्गिझतान की ओर कर रहे हैं रुख



विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक कॉलेज के अनुभव को पूरे देश की स्थिति का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, लिकिन यह संकेत जरूर देता है कि यदि और अप्रिय देश अपने विभिन्न विद्यालयों के लिए सुरक्षित और अप्रियता के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

मेडिकल शिक्षा की उगणवाता का मूल्यांकन केवल फोस या किसी विदेशी मान्यता से नहीं, बल्कि छात्रों के विदेशी मान्यता से विचार करते हैं। सूक्ष्म विद्यालयों में विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं। एसें में छात्रों को एजेंटों के द्वारा केवल विदेशी विद्यालयों को अपना रखा जाता है। जिसमें विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

पाकिस्तानी निवेशकों द्वारा संचालित कुछ संस्थान, जो किर्गिझतान में कम प्रभावी हैं। इसके विदेशी विद्यालयों में विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विदेशी विद्यालयों के बीच विकल्प उपलब्ध हैं।

यहाँ पूर्ण छात्रों को विद

